केंद्रीय योजनागत परिव्यय में हुई कमी की, राज्य योजनागत सेक्टर में आवंटन बढ़ने से, कुछ हद तक, पूर्ति हो गई है ।

निधियों का दुरुपयोग किया जाना

3343. **श्री राजूभाई ए. परमार :**
श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुदान प्राप्त करने वाली कुछ संस्थायें उसका उचित ढंग से उपयोग नहीं करती है जिसके कारण सरकारी धन का दुरुपयोग होता है और शैक्षिक योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने संगठनों का पता लगाया गया है ; और

(ग) उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश पर पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, को अनुदान दिए जाते । तथापि, संयुक्त मूल्यांकन दल, जिनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और बाहर के विशेषज्ञ होते हैं, इन स्वैच्छिक संगठनों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। संयुक्त मूल्यांकन दलों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 86 स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया था । इसी प्रकार, गैर-औपचारिक शिक्षा को योजना के अंतर्गत, अब तक एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया था । इन मामलों में दिए गए अनुदानों की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

गांवों में युवा विकास केन्द्र

3344. **श्री ईश दत्त यादव :** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक 10 गांवों के लिए एक युवा विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों में किये जाने वाले प्रस्ताविक कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत किन-किन गांवों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कु. ममता बनर्जी) :
(क) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक दस गांवों के समूह के लिए एक की दर से 18,000 युवा विकास केन्द्र प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) इन युवा विकास केन्द्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए सूचना, खेल, प्रशिक्षण तथा युवा कार्यक्रमों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी । केन्द्र के लिए भूमि सम्बन्धित पंचायतों द्वारा दान की जायेगी। पारस्परिक श्रम तथा सामग्री की आपूर्ति के माध्यम से प्रत्येक केन्द्र के लिए भवन और बुनियादी खेल सुविधाओं का निर्माण आरम्भ किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र का प्रबंध संघटक गांवों के युवाओं से गठित की गई युवा समितियों द्वारा किया जायेगा। संचालन और रखरखाव संबंधी व्यय की उगाही समिति करेगी ।

(ग) किन-किन गांवों में कितने युवा विकास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि यह मामला वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

से सम्बन्धित है। तथापि सरकार इसी वर्ष शुरूआत करना चाहती है। यह सुनिश्चत किया जायेगा कि युवा विकास केन्द्रों का सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समान वितरण हो।

Female Literacy

3345. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) literacy rate in general in various States of the country at present;

(b) literacy rate among women in different States of the country at present;

(c) whether Government propose to incorporate population study in the literacy programme for women;

(d) if so, by when it is likely to be finalised; and

(e) the amount earmarked for women literacy programme during the Eighth Plan?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) A statement showing literacy rate State-wise of all persons and women for the population aged 7 years and above, according to the provisional figures of 1991 census is attached. (See below).

(c) and (d) The issues relating to population education from an important component of the adult education programme. They are reflected in the teaching/learning material significantly. Apart from this, a UNFPA funded 'Population Education Project' is being implemented in 15 States where the population education component specifically incorporated in the adult education programme. In addition, the Total Literacy Campaigns which now constitute the dominant strategy for eradication of illiteracy under the National Literacy Mission are also the campaigns for maternity protection and child care and propagation of small family norms.

(e) No separate allocations are made in the literacy Programme for women. During the Eighth Five Year Plan, a tentative allocation of Rs. 1400 crores has been made in the Central Sector and Rs. 407.67 crores in the State Sector for the adult literacy programmes.

Statement

Percentage of literates to Estimated population aged 7 Years and above

Sl.No.	States/UTs.	1991	
		Persons	Females
1	2	3	4
	INDIA	52.11	39.42
	States		
	Andhra Pradesh	45.11	33.71
2	Arunachal Pradesh	41.22	29.37
3	Assam	53.42	43.70
4	Bihar	38.54	23.10
5	Goa	76.96	68.20